



2026:AHC:65756

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5504 वर्ष 2026

मुकेश यादव और अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: हरीश यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदकों के अधिवक्ता श्री हरीश यादव और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदकों की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उन्हें मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना-दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में दर्ज यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 (1) के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक गैंग चार्ट में उनके खिलाफ दिखाए गए दो मामलों में ज़मानत पर हैं और उपरोक्त के अलावा आवेदक संख्या-1 के पास चार अन्य मामले हैं और वह सभी चार मामलों में ज़मानत पर हैं। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक, जो 9.1.2026 से जेल में बंद हैं, वचन देते हैं कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है तो वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. तत्स्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों को ज़मानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक गिरोह चार्ट में उनके खिलाफ दिखाए गए दो मामलों में ज़मानत पर हैं और उपरोक्त के अलावा आवेदक संख्या-1 पर चार अन्य मामले हैं और वह सभी चार मामलों में ज़मानत पर है। आवेदक 9.1.2026 से जेल में बंद हैं।

6. अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के पूर्वाग्रह को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदकों- मुकेश यादव और गौरव को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे।

(iii) आवेदक निम्नलिखित के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे: (i) मामले को खोलना, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन दाखिल करेंगे कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)